देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 16.01.2025
समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने और आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए राज्य के सात जिलों में 30 जनवरी को मॉक ड्रिल की जाएगी।
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना।

दुर्घटना बीमा लाभ निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं के बाद सभी यात्रियों के परिजनों को समान राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को 10 दिनों के भीतर इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही परिवहन निगम की ओर से भी 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब यह लाभ निजी बस यात्रियों को भी मिलेगा, जिससे दुर्घटनाओं के दौरान उनके परिजनों को कुल 10 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी।

श्री धामी ने सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़कों पर इंफोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस जांचने, ड्राइवरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने और क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया को तेज करने को भी कहा गया है।

महिला सशक्तीकरण

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को उनकी क्षमता और समर्पण के लिए सही दिशा मिले, तो वे राज्य और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे सकती हैं।राजभवन में दून

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने वन यूनिवर्सिटी–वन रिसर्च योजना के तहत उत्तराखंड में महिलाओं के जीवन और आजीविका में सुधार पर चल रहे शोध कार्य की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की शोध टीम ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता जैसे विषयों पर डेटा एकत्र कर गहन अध्ययन किया है। इसके अलावा, उद्यमिता, आजीविका विविधीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभाव जैसे मुद्दों का भी विश्लेषण किया गया। राज्यपाल ने शोध कार्य की सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस शोध के अंतिम निष्कर्षों को सरकार के साथ साझा किया जाएगा ताकि ठोस नीतियां बनाई जा सकें।

चाय उत्पादन

पिथौरागढ़ जिले में चाय उत्पादन और पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिये ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि वर्तमान में जिले में चाय उत्पादन के लिए सीमित क्षेत्र उपलब्ध हैं, लेकिन इन क्षेत्रों का विस्तार और विकास करने की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके लिये आयुक्त ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को क्लस्टर आधारित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश गए हैं। कुमाऊं आयुक्त ने नायल और पाखू समेत आसपास के गांवों में मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से चाय उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर काम करने को कहा।

पीसीएस मुख्य परीक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा दो फरवरी से शुरू होगी। आयोग ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न केंद्रों पर दो से पांच फरवरी के बीच होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर 17 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे। वही आयोग ने लोअर पीसीएस परीक्षा के आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे 20 जनवरी तक आवेदन में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं।

मॉक ड्रिल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने और आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए 30 जनवरी को मॉक ड्रिल आयोजित करने की योजना बनाई है। यह अभ्यास इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) के दिशा–निर्देशानुसार किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के तहत सात संवेदनशील जिलों के 17 स्थानों पर अभ्यास किया जाएगा। एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र की सराहना करते हुए कहा कि पिछले वर्ष अल्मोड़ा और नैनीताल में वनाग्नि पर बेहतर नियंत्रण किया गया।

गौरतलब है कि मॉक ड्रिल में फायर फाइटर्स, ड्रोन, सेटेलाइट फोन और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्थानीय समुदायों और एनजीओ की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हैं। राजधानी देहरादून सहित आज तड़के प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हुई। राज्य के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी हुआ है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज राज्य के दो हजार पांच सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

इधर, कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और पाला पड़ने के चलते सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत नमक और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। कुमाऊं आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को बर्फबारी से प्रभावित सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए बर्फ और मलबा हटाने वाली मशीने और गैंग की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।

समान नागरिक संहिता

प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता– यू०सी०सी कानून लागू किया जाएगा। ऋषिकेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनवरी के महीने में ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा।

इस बीच, बागेश्वर में जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता ऑनलाईन पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर राजस्व अधिकारियों, ब्लाक व नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्मिकों से यूसीसी पोर्टल के सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारियां प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से सीखनें का आह्वान किया ताकि आने वाले समय में वे अन्य लोगों को भी यूसीसी के संबंध में जानकारी दे सकें।

आई गॉट कर्मयोगी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सरकार के सभी कार्मिकों को मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास के लिए आई गॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से शत–प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कानूनों की जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक जानकारी और जागरूकता पहुंचाने के लिए

विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया, ताकि नागरिक अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ ले सकें।

निकाय चुनाव

प्रदेश में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी घर–घर जाकर मतदाओं को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जनसभाएं, रोड शो और पदयात्रा के जरिये भी चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी में रोड शो करेंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांतिदल और स्वतंत्र उम्मीदवार भी जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं।

अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के नगर निगम चुनाव के संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है– भाजपा ने रखा उत्तराखंड के शहरों के विकास का रोडमैप, मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के लिये प्रदेश स्तर पर एक और 11 नगर निगमों के लिये जारी किये संकल्प पत्र। इसी समाचार पर राष्ट्रीय सहारा मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है– संकल्प पत्र विकास की गारंटी।

निजी बस हादसे में उत्तराखंड सरकार अब रोडवेज बस हादसों के ''समान मुआवजा देगी। इस ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है– निजी बसों की सवारियों को भी दुर्घटना बीमा आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

भूस्खलन जोन व जंगल की आग जैसे मुद्दों का अध्ययन करेंगे छात्र। दैनिक जागरण समाचार पत्र के अनुसार एस.सी.ई.आर.टी की ओर से इसके लिये रूपरेखा तैयार की जा रही है।

पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह आसान। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला की ख़बर है– केंद्रीय मंत्रालय ने दी छूट, अब रोपवे के पिलर की वन भूमि का ही करना होगा हस्तांतरण।